+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(17 February 2025)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- यूक्रेन के मुद्दे पर आपातकालीन 'यूरोपीय शिखर सम्मेलन' का आयोजन
- 'सॉवरेन ग्रीन बांड' क्या होते हैं, भारत में ऐसे बांडों की मांग कमजोर क्यों है?
- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDKY) क्या है?
- MCQ

यूक्रेन के मुद्दे पर आपातकालीन 'यूरोपीय शिखर सम्मेलन' का आयोजन:

चर्चा में क्यों है?

- फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने 17 फरवरी को यूक्रेन युद्ध पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सहित यूरोपीय नेताओं की मेजबानी करने का निर्णय लिया है।
- उल्लेखनीय है कि यह आपातकालीन शिखर सम्मेलन अमेरिका द्वारा यह सुझाव दिए जाने के बाद आयोजित किया जा रहा है कि यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए किसी भी वार्ता में यूरोप की कोई भूमिका नहीं होगी।
- इस शिखर बैठक में फ़्रांस के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के अतिरिक्त जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़, पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क, नाटो महासचिव मार्क रूटे, इतालवी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी और यूरोपीय संघ से उर्सुला वॉन डेर लेयेन और एंटोनियो कोस्टा भी शामिल होंगे।

यह बैठक क्यों आयोजित की जा रही है?

- उल्लेखनीय है कि इस शिखर सम्मेलन में यूरोपीय नेताओं द्वारा यूक्रेन के प्रति अमेरिकी दृष्टिकोण में आए उथल-पुथल भरे बदलाव तथा यूरोपीय महाद्वीप की सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरों पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है।
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पिछले सप्ताह नाटो और यूक्रेन में यूरोपीय सहयोगियों को चौंका दिया जब उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बिना उनसे परामर्श किए बातचीत की है और शांति प्रक्रिया शुरू करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के यूक्रेन दूत कीथ केलॉग ने 15 फरवरी को यूरोप को और झटका दिया जब उन्होंने कहा कि यूक्रेन शांति वार्ता के लिए उसे टेबल पर जगह नहीं मिलेगी।
- हालांकि यूरोपीय नेताओं की ओर से इस पर तत्काल प्रतिक्रिया हुई। फ़िनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा कि "यूरोपीय लोगों के बिना यूक्रेन, यूक्रेन के भविष्य या यूरोपीय सुरक्षा संरचना के बारे में चर्चा या बातचीत करने का कोई तरीका नहीं है....लेकिन इसका मतलब है कि यूरोप को अपने काम को एक साथ करने की ज़रूरत है। यूरोप को कम बात करने और ज्यादा काम करने की ज़रूरत है"।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

यूक्रेन, यूरोप 'वास्तविक' शांति वार्ता का हिस्सा होंगे:

- हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रुबियो ने रूस और अमेरिका के बीच सऊदी अरब में आने वाले दिनों में होने वाली प्रारंभिक वार्ता से बाहर रखे जाने की यूरोपीय चिंताओं को कमतर आंका है।
- एक साक्षात्कार में, विदेश मंत्री रुबियो ने कहा कि वार्ता प्रक्रिया अभी तक गंभीरता से शुरू नहीं हुई है, और यदि वार्ता आगे बढ़ती है, तो यूक्रेनी और अन्य यूरोपीय नेताओं को इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन हम अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं।

'सॉवरेन ग्रीन बांड' क्या होते हैं, भारत में ऐसे बांडों की मांग कमजोर क्यों है?

परिचय:

- भारत ने भी कई उभरते बाजारों की तरह कम कार्बन अर्थव्यवस्था में अपने संक्रमण को वित्तपोषित करने के लिए 'सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड' की ओर रुख किया, लेकिन निवेशकों की मांग कमजोर बनी हुई है।
- जबकि ग्रीन बॉन्ड सरकारों को स्वच्छ ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के लिए पूंजी जुटाने में मदद करते हैं, भारत ने एक सार्थक 'ग्रीनियम' - आमतौर पर ऐसे बॉन्ड से जुड़ी कम उधारी लागत - हासिल करने के लिए संघर्ष किया है। नतीजतन, ग्रिड-स्केल सोलर सहित प्रमुख योजनाओं के लिए नियोजित आवंटन में कटौती की गई है।

ग्रीन बॉन्ड एवं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं?

- ग्रीन बॉन्ड विभिन्न सरकारों, निगमों और बहुपक्षीय बैंकों द्वारा कार्बन उत्सर्जन को कम करने या जलवायु लचीलापन बढ़ाने वाली परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के

लिए जारी किए गए ऋण साधन हैं। वहीं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (SGrB) वे ग्रीन बॉन्ड होते हैं जो भारत सरकार जैसी संप्रभु संस्थाओं द्वारा जारी किए जाते हैं।

- बॉन्ड जारीकर्ता आम तौर पर पारंपरिक बॉन्ड की तुलना में कम यील्ड (रिटर्न) पर ग्रीन बॉन्ड की पेशकश करते हैं, क्योंकि इसके जरिये निवेशकों को आश्वस्त करते हैं कि बांड से प्राप्त राशि का उपयोग विशेष रूप से 'ग्रीन निवेश' के लिए किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि बॉन्ड यील्ड (रिटर्न) में यह अंतर - जिसे 'ग्रीन प्रीमियम या ग्रीनियम' के रूप में जाना जाता है - ग्रीन बॉन्ड के लागत लाभ को निर्धारित करता है। एक उच्च ग्रीनियम जारीकर्ताओं को कम लागत पर धन जुटाने की अनुमति देता है, जिससे ग्रीन निवेश अधिक आकर्षक हो जाता है।
- ग्रीन बॉन्ड ने निवेश करने वाले अक्सर सतत, दीर्घकालिक रिटर्न चाहते हैं, और उनके पास अपने फंड का एक हिस्सा ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए आवंटित करने के लिए आंतरिक या बाहरी जनादेश भी हो सकते हैं।

भारत सरकार द्वारा 'सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड' क्यों जारी किया जाता है?

- भारत सरकार ने 2022 में 'सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड' जारी करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है। यह रूपरेखा "ग्रीन प्रोजेक्ट्स" को उन परियोजनाओं के रूप में परिभाषित करती है जो संसाधन उपयोग में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करती हैं,

कार्बन उत्सर्जन को कम करती हैं, जलवायु लचीलापन को बढ़ावा देती हैं और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करती हैं।

- वित्त वर्ष 2022-23 से, भारत ने आठ बार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं, और लगभग 53,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। प्रत्येक वर्ष, भारत सरकार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड से प्राप्त आय का लगभग 50% रेल मंत्रालय के माध्यम से ऊर्जा कुशल तीन-चरण इलेक्ट्रिक इंजनों के उत्पादन को निधि देने के लिए उपयोग करती है।
- वर्ष 2024-25 के लिए, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के तहत पात्र योजनाओं के लिए आवंटन के संशोधित अनुमानों में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विनिर्माण के लिए 12,600 करोड़ रुपये, मेट्रो परियोजनाओं के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 4,607 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय हरित भारत मिशन के तहत वनरोपण के लिए 124 करोड़ रुपये शामिल हैं।

भारत में 'सॉवरेन ग्रीन बांड' को लेकर निवेशक उत्साहित क्यों नहीं हैं?

- उल्लेखनीय है कि भारत के 'सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड' इश्यू को निवेशकों की कम मांग के कारण गति प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ा है, जिससे सरकार के लिए 'ग्रीनियम' हासिल करना मुश्किल हो गया है। विदेशी निवेशकों के लिए नियमों को

आसान बनाने सहित प्रयासों के बावजूद, नीलामी में सीमित भागीदारी देखी गई है, जिसमें बॉन्ड अक्सर प्राथमिक डीलरों को हस्तांतरित हो जाते हैं। जबकि वैश्विक स्तर पर ग्रीनियम 7-8 आधार अंकों तक पहुँच गया है, भारत में यह अक्सर केवल 2-3 आधार अंकों पर होता है। यह 'सॉवरेन ग्रीन बांड' के व्यवहार्य फंडिंग स्रोत के रूप में विस्तार को सीमित करता है।

- विशेषज्ञों के अनुसार इससे जुड़ी एक प्रमुख चुनौती तरलता है। इन बांडों के छोटे इश्यू आकार और निवेशकों के लिए परिपक्वता तक बॉन्ड रखने की बाध्यता ने द्वितीयक बाजार में इनके व्यापार को रोक दिया है, जिससे उनकी अपील कम हो गई है। इसके अतिरिक्त, भारत में सामाजिक प्रभाव निधि और जिम्मेदार निवेश जनादेश के एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का अभाव है, जो अन्य बाजारों में ग्रीन बॉन्ड की मांग को बढ़ाता है।

'सॉवरेन ग्रीन बांड' को लेकर कम उत्साह मायने क्यों रखता है?

- उल्लेखनीय है कि 'सॉवरेन ग्रीन बांड' से पर्याप्त आय जुटाने में सरकार की असमर्थता इसके तहत पात्र योजनाओं के लिए वित्त पोषण को प्रभावित करती है और कमी को पूरा करने के लिए राजकोष पर दबाव बढ़ाती है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- शुरुआत में, 2024-25 के लिए 'सॉवरेन ग्रीन बांड' आय से अनुमानित वित्त पोषण की आवश्यकता 32,061 करोड़ रुपये थी। हालांकि, 'सॉवरेन ग्रीन बांड' को बेचने के असफल प्रयासों के बाद, संशोधित अनुमान को घटाकर 25,298 करोड़ रुपये कर दिया गया है। नतीजतन, ग्रिड-स्केल सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए आवंटन 10,000 करोड़ रुपये से घटाकर 1,300 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- वहीं चालू वित्त वर्ष में अपेक्षित आय में कमी को पूरा करने के लिए, सरकार के सामान्य राजस्व से लगभग 3,600 करोड़ रुपये निकाले जाएंगे।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDKY) क्या है?

'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDKY)':

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित होकर राज्यों के साथ साझेदारी में 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDKY)' शुरू करने की घोषणा की।
- उल्लेखनीय है कि मौजूदा योजनाओं और विशेष उपायों के अभिसरण के माध्यम से, यह कार्यक्रम कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को कवर करेगा। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) की तर्ज पर:

- वित्त मंत्री सीतारमण ने इस कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा था कि "आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) की सफलता से प्रेरित होकर हमारी सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में PMDKY शुरू करेगी"।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) क्या है?

- उल्लेखनीय है कि 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य 3 C - Convergence (अभिसरण: केंद्रीय और राज्य योजनाओं का), Collaboration (सहयोग: केंद्रीय और राज्य स्तर के नोडल अधिकारियों और जिला कलेक्टरों का) और Competition (प्रतिस्पर्धा: मासिक डेल्टा रैंकिंग के माध्यम से जिलों के बीच) के आधार पर भारत भर के 112 सबसे कम विकसित जिलों को तेज़ी से और प्रभावी रूप से बदलना था।
- यह रैंकिंग 5 व्यापक सामाजिक-आर्थिक विषयों - स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और बुनियादी ढाँचा - के तहत 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों में की गई वृद्धिशील प्रगति पर आधारित है।

योजना के तहत कवर किए जाने वाले जिलों के लिए मापदंड:

- वित्त मंत्री के अनुसार, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना तीन व्यापक मापदंडों: कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण पैरामीटर, के आधार पर 100 जिलों को कवर करेगा। वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्रालय इन

मापदंडों का डेटा एकत्र कर रहा है, जिसके आधार पर जिलों की पहचान की जाएगी।

- उल्लेखनीय है कि फसल तीव्रता एक माप है कि भूमि का कितनी कुशलता से उपयोग किया जाता है, और इसे कुल फसल क्षेत्र और शुद्ध बोए गए क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। अखिल भारतीय स्तर पर, 2021-22 में फसल तीव्रता 155% दर्ज की गई, हालांकि यह आंकड़ा राज्य दर राज्य काफी भिन्न है।
- कृषि मंत्रालय ने वित्तीय सेवा विभाग और नाबार्ड से जिलेवार कृषि ऋण पर डेटा साझा करने का अनुरोध किया है।

PMDKY का उद्देश्य और बजटीय आवंटन:

- वित्त मंत्री के अनुसार, PMDKY कार्यक्रम के निम्नलिखित पाँच उद्देश्य हैं:

1. कृषि उत्पादकता बढ़ाना;

2. फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना;

3. पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण को बढ़ाना;

4. सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना; और

5. दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- **बजटीय आवंटन:** उल्लेखनीय है कि बजट दस्तावेजों में योजना के लिए अलग से आवंटन का प्रावधान नहीं है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि कृषि मंत्रालय, मत्स्य पालन मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं से धन लिया जाएगा। केंद्र सरकार इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा औपचारिक रूप से मंजूरी दिए जाने के बाद और ज़मीन पर लागू करने से पहले योजना के लिए आवंटन कर सकती है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

MCQs

1. चर्चा में रहे 'सॉवरेन ग्रीन बांड' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

   1. ये विभिन्न सरकारों, निगमों और बहुपक्षीय बैंकों द्वारा कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए जारी किए गए ऋण साधन हैं।
   2. इसके तहत बॉन्ड जारीकर्ता आम तौर पर पारंपरिक बॉन्ड की तुलना में अधिक बॉन्ड यील्ड पर ग्रीन बॉन्ड की पेशकश करते हैं।

   उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   (a) केवल 1

   (b) केवल 2

   (c) 1 और 2 दोनों

   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

   Ans:(d)

2. भारत सरकार द्वारा 'सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड' जारी करने के लिए एक रूपरेखा कब जारी की गयी थी?

   (a) 2021 में

   (b) 2022 में

   (c) 2023 में

   (d) 2024 में

   Ans:(b)

3. भारत सरकार द्वारा जारी सॉवरेन ग्रीन बांड को लेकर निवेशकों में उत्साह की कमी के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इन बॉन्डों के छोटे इश्यू आकार और निवेशकों के लिए परिपक्वता तक बॉन्ड रखने की बाध्यता।
2. भारत में सामाजिक प्रभाव निधि और जिम्मेदार निवेश जनादेश के एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का अभाव है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans:(c)

4. भारत सरकार ने बजट 2025-26 में राज्यों के साथ साझेदारी में 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' शुरू करने की घोषणा की गयी है। इस योजना के लिए कितना बजटीय आवंटन किया गया है ?

(a) 25,298 करोड़ रुपये

(b) 10,000 करोड़ रुपये

(c) 32,061 करोड़ रुपये

(d) बजट में इस योजना के लिए अलग से आवंटन का प्रावधान नहीं है।

Ans:(d)

5. हाल ही में चर्चा में रहे 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इस कार्यक्रम की शुरुआत जनवरी 2018 में किया गया था।
2. इस कार्यक्रम का उद्देश्य अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा के आधार पर भारत के सबसे अधिक निर्यात करने वाले जिलों को और तेज़ी से विकसित करना।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans:(a)